eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

विकसित भारत @ 2047 तथा आधार संरचना की भूमिका

डॉ पंकज सिंह[1]
[1]एसोसिएट प्रोफेसर – अर्थशास्त्र, महामाया राजकीय महाविद्यालय धनुपुर, हँड़िया, प्रयागराज (उ0प्र0)

Received: 08 November 2025, Accepted: 20 November 2025, Published online: 30 November 2025

Abstract

विकसित भारत पहल भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह पहल शासन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। विकसित भारत पहल का उद्देश्य वर्ष 2047 तक, जो इसकी स्वतंत्रता की शताब्दी होगी, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। यह पहल युवाओं को सशक्त बनाने और सतत विकास प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बुनियादी ढाँचा विकास आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण को बढ़ाने और व्यवहार्य विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः एक बहु–क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें परिवहन, ऊर्जा, जल संसाधन, दूरसंचार और शहरी विकास जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हों। संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने, टिकाऊ और लचीले बुनियादी ढाँचे के साथ दोहराव को कम करने के लिए इन क्षेत्रों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है।

डिजिटलीकरण, स्मार्ट तकनीकों और डेटा एनालिटिक्स को अपनाने से बुनियादी ढाँचे के संचालन को अनुकूलित किया जा सकता है, सेवा वितरण में सुधार किया जा सकता है और नियोजन एवं प्रबंधन प्रक्रियाओं में साक्ष्य–आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सकता है। इसके लिए उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है जो हाशिए पर पड़े समुदायों को लाभान्वित करें, बुनियादी सेवाओं तक पहुँच बढ़ाएँ और विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के संसाधनों के समान वितरण को बढ़ावा दें। परस्पर जुड़ी परियोजनाओं के साथ समन्वित शासन विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देगा जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और साथ ही अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना, नियामक ढाँचों को सुव्यवस्थित करना और सार्वजनिक–निजी भागीदारी को बढ़ाना प्रभावी परियोजना वितरण को सुगम बना सकता है। साथ ही, विकासशील भारत में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए घरेलू प्रयासों को पूरक बनाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रणनीतिक साझेदारियों में शामिल होना, वैश्विक विशेषज्ञता तक पहुँचना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण जुटाना बुनियादी ढाँचे के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी ला सकता है।

मुख्य शब्द– बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी, विकास, नवाचार , आर्थिक वृद्धि

Introduction

विकसित भारत @ 2047, भारत सरकार का विजन है जिसका उद्देश्य 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जो स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। यह समावेशी विकास, नवाचार, स्थिरता और सुशासन पर केंद्रित है, जिससे समाज के हर वर्ग की समृद्धि सुनिश्चित होती है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

मुख्य विशेषताएँ –

- लक्ष्य – वर्ष 2047 तक, भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी।
- मुख्य स्तंभ – युवा, गरीब, महिलाएँ और किसान।
- आर्थिक लक्ष्य – दो दशकों में 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था।
- प्राथमिकता वाले क्षेत्र – शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढाँचा, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, सामाजिक कल्याण।
- भागीदारी–नागरिक MyGov पोर्टल के माध्यम से अपने विचार दर्ज करा सकते हैं।

विकसित भारत 2047 क्या है?

विकसित भारत का अर्थ है– विकसित भारत @ 2047, 2047 में स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का विजन है। यह विजन चार स्तंभों पर आधारित है – युवा, गरीब, महिलाएं और अन्नदाता।

विकसित भारत @ 2047, 2047 में स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक विकसित राष्ट्र बनने का भारत का महत्वाकांक्षी विजन है। हालांकि एक मजबूत योजना लागू है, लेकिन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के मुद्दों को संबोधित करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा। पिछले एक दशक में भारत का बुनियादी ढांचा विकास इसकी आर्थिक कहानी की एक परिभाषित विशेषता रही है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में, भारत ने बुनियादी ढांचे को समावेशी विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता के एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में मान्यता दी है। देश ने भौतिक और डिजिटल परिसंपत्तियों के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है ।

111 ट्रिलियन रुपये के प्रारंभिक अनुमानित निवेश के साथ राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जैसी पहलों ने सभी क्षेत्रों में एकीकृत और समन्वित अवसंरचना विकास की नींव रखी है। इन प्रयासों का उद्देश्य पारदर्शिता में सुधार, परियोजना में देरी को कम करना और अंतर–मंत्रालयी सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे राष्ट्र निर्माण के लिए एक अधिक रणनीतिक दृष्टिकोण सक्षम हो सके। कुछ आँकड़े देने के लिए, वित्त वर्ष 2024 तक, केंद्र सरकार का अवसंरचना व्यय के लिए बजट आवंटन 10 ट्रिलियन रुपये तक पहुँच गया, जिसमें अकेले सड़कों पर पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2014 से 5.7 गुना (निजी निवेश सहित) बढ़कर 3.01 ट्रिलियन रुपये हो गया। राजमार्ग निर्माण की गति वित्त वर्ष 2015 में 12.1 किमीधदिन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 33.8 किमी/ दिन हो गई स्मार्ट सिटीज मिशन ने 8,067 क्रॉस–सेक्टरल परियोजनाओं में से 94:2 को पूरा कर लिया है, जिसमें मार्च 2025 तक भारत सरकार द्वारा लगभग 47,385 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) जैसी पहलों के साथ, पीएम आवास योजना (PMAY) और जल जीवन मिशन ने आवास, पानी, स्वच्छता और गतिशीलता तक पहुंच को बढ़ाया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, पीएम ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और भारतनेट जैसे कार्यक्रमों ने कनेक्टिविटी का विस्तार किया है, जिससे शहरी–ग्रामीण विभाजन को पाटने में मदद मिली है। भारत का डिजिटल बुनियादी

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

ढांचा भी वैश्विक मानक के रूप में उभरा है, जिसमें आधार, UPI और डिजिटल इंडिया पहल सेवा वितरण और वित्तीय समावेशन को बदल रही है। इन उपलब्धियों के बावजूद, कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। शहरी बुनियादी ढाँचा जनसंख्या वृद्धि से पीछे चल रहा है, सार्वजनिक संसाधनों को निजी क्षेत्र की भागीदारी से बढ़ाने की आवश्यकता है, हालाँकि, नियामक जोखिम और लंबी परियोजना निर्माण अवधि जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भूमि अधिग्रहण में देरी और पर्यावरणीय मंजूरी जैसी कार्यान्वयन बाधाएँ प्रगति में और बाधा डालती हैं। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है, क्योंकि बुनियादी ढाँचा चरम मौसम की घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील है और पर्याप्त लचीलेपन के उपायों का अभाव है। साथ ही, भारत उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। हरित बुनियादी ढाँचे की ओर वैश्विक बदलाव 2070 तक भारत की शुद्ध–शून्य प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता और टिकाऊ निर्माण में निवेश के अवसर पैदा करता है। 5G, डेटा सेंटर और AI सहित डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विस्तार, रसद, शहरी प्रबंधन और सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांति लाने की क्षमता प्रदान करता है।

भारतमाला, सागरमाला और समर्पित माल गलियारों (DFC) जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क में सुधार हो रहा है, और आर्थिक क्षमता को उजागर कर रहे हैं। उदार FDI मानदंड और परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम भी निजी निवेश के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं। गति शक्ति जैसे प्लेटफॉर्म डेटा–आधारित निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं, जबकि मिश्रित वित्त मॉडल और ग्रीन बॉन्ड निजी पूँजी को बढ़ावा दे सकते हैं। जलवायु जोखिम आकलन, निम्न–कार्बन प्रौद्योगिकियाँ और प्रकृति–आधारित समाधान मानक अभ्यास बनने चाहिए। शासन को मजबूत करना, शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना और वास्तविक समय की निगरानी और पूर्वानुमानित रखरखाव के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना आवश्यक होगा। आज रणनीतिक विकल्प चुनकर, भारत ऐसे बुनियादी ढाँचे का निर्माण कर सकता है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए और पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित करेकृजिससे 2047 तक एक सच्चे विकसित और समावेशी राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त होगा।

2047 तक "विकसित भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढाँचे का विकास महत्वपूर्ण है, जिसमें आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी और जीवन की बेहतर गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत भौतिक, डिजिटल और सामाजिक नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

प्रमुख रणनीतियों में पीएम गति शक्ति जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना, परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाना और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में स्थिरता और लचीलेपन पर जोर देना शामिल है। सड़क और रेल नेटवर्क में सुधार, डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार और स्मार्ट शहरों का विकास जैसी पहलें देश भर में विभाजन को पाटने और समावेशी विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। विकसित भारत विजन समावेशी और टिकाऊ अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए है, जिसमें भौतिक (सड़क, रेलवे, बंदरगाह) और डिजिटल (एआई, डेटा प्लेटफॉर्म) पहलू शामिल हैं।

इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, रणनीतियाँ बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने, सार्वजनिक–निजी भागीदारी को बढ़ावा देने, भूमि अधिग्रहण और कुशल श्रम जैसी

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

चुनौतियों का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं कि विकास एक बढ़ते राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने और 2047 तक उच्च आय का दर्जा हासिल करने के लिए टिकाऊ और जलवायु–लचीला हो।

निष्कर्ष– यदि भारत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निर्धारित 5 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो मान्यता पाँच अग्रणी राज्यों से आगे बढ़कर अन्य राज्यों को भी योगदान देना होगा । अर्न्स्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड (EY) ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और केरल सहित अगले राज्यों की पहचान की है। हालाँकि, 1 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करना प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी होगी, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी एक बड़ी बाधा है। कई अर्थशास्त्रियों का मत है कि निर्यात पर अत्यधिक निर्भर राज्यों को मौजूदा वैश्विक आर्थिक सुस्ती के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

इसके अतिरिक्त, कृषि की तुलना में सकल राज्य मूल्य वर्धित (GSVA) में सेवाओं और उद्योग की हिस्सेदारी को उत्तरोत्तर बढ़ाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि यह उत्पादन और रोजगार वृद्धि दोनों के लिए फायदेमंद होगा। फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संस्थापक निदेशक राहुल अहलूवालिया इस बात पर जोर देते हैं कि भारत जैसे देश में तेज विकास के लिए निर्यात एक महत्वपूर्ण जरिया है। 2022 में वैश्विक व्यापारिक निर्यात 25.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने के बावजूद, भारत की हिस्सेदारी केवल 1.8ः ही थी।

अहलूवालिया भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की वकालत करते हैं, जिसका लक्ष्य वैश्विक निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है। इस रणनीति से पिछले दो दशकों में आईटी और आईटीईएस क्षेत्रों की सफलता के समान विकास में तेजी आने की उम्मीद है। नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने अक्टूबर में अगले दशक के लिए एक रणनीति तैयार करने का संकेत दिया था। भारत का लक्ष्य 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलना है।

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना हमारा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हमें वित्तीय वित्तपोषण, जलवायु परिवर्तन, आईटी–सक्षम सेवाएँ, आवास, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और दूरसंचार जैसे कारकों को नहीं भूलना चाहिए।

सन्दर्भ सूची -

[1] The Infrastructure Finance Challenge & A Report by the Working Group on Infrastructure Finance Stern School of Business- New York University

[2] Journal of Infrastructure, Policy and Development ISSN:2572&7923 Print, 2572-7931 Online, Journal abbreviation: J- Infras- Policy- Dev-

[3] Climate Change and Infrastructure, Urban Systems, and Vulnerabilities: Technical Report for the U-S-Department of Energy in Support of the National Climate Assessment & Thomas J- Wilbanks and Steven Fernandez, Island Press, 2014, eISBN: 978-1-61091-556-4, Paper: 978-1-61091-554-0

[4] Rengalakshmi, S-, & Ravindran, K- 2023- Exploring the Influence of Customer Expectations and Perceptions in Green Shopping Decisions- International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering] 11,1s, 179-182-

[5] Ramalakshmi K- & Ravindran, K- 2022- Influence of citizenship behaviour in the workplace on achieving organisational competitiveness- polish Journal of Management Studies, 25,2, 247-265-

[6] Priyanka, R-, Ravindran, K-, Sankaranarayanan, B-, & Ali, S- M- Challenges to Human Resource Practices in Startup Companies: Implications for Economic and Social Sustainability at the Workplace- Available at SSRN 4186769

[7] Gayathiri, M- B-,- Ravindran, K- 2020- Importance Of Digital Marketing Awareness In Indian Market With Special Reference To Tamilnadu- Journal of Critical Reviews, 7-15-, 4015-4020-

[8] Dhesinghraja, J-, & Sendhilkumar, M- ,2015,- An Overview of Supply Chain Management on Apparel Order Process in Garment Industries, Bangalore- Journal of Exclusive Management Science